



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 17, 2003/वैशाख 27, 1925

No. 13]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 2003/VAISAKHA 27, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2003

आ. अ. 31.—यतः, श्री राजेश सिंह, जो फरवरी, 2002 में 277-सरसौल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन में, एक अभ्यर्थी थे, को, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें यह सूचित किया गया था कि उक्त अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10(क) के अन्तर्गत, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, दिनांक 7 नवम्बर, 2002 के अपने आदेश सं. 76/उ.प्र.-वि.स./2002 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर, उस आदेश की तारीख से अगले तीन वर्षों के लिए निरर्हित किया गया था; और

यतः, श्री राजेश सिंह ने दिनांक रहित एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें आयोग की ओर से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ; और

यतः रिकार्ड के अनुसार, आयोग का दिनांक 15 जुलाई, 2002 का नोटिस उनकी बहन सुश्री रीतू सिंह द्वारा 10 अगस्त, 2002 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, उपलब्ध तथ्यों और सूचना के आधार पर अभ्यावेदन के गुणावगुण पर विचार करते हुए निर्वाचन आयोग ने श्री राजेश सिंह द्वारा की गई अपील ठुकरा दी; और

यतः, श्री राजेश सिंह ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अन्तर्गत पुनः अपील की और अनुरोध किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10(क) के अधीन आयोग के 7 नवम्बर, 2002 के आदेश द्वारा उन पर लगाई गई निरर्हता हटा ली जाए; और

यतः, दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को की गई नई अपील में दी गई सूचना पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने निर्णय लिया कि श्री राजेश सिंह को एक मौका देते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाए और 5 फरवरी, 2003 को सुनवाई निश्चित की; और

यतः, 5 फरवरी, 2003 को श्री राजेश सिंह को सुनने के बाद आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्री राजेश सिंह द्वारा निर्वाचन व्ययों को लेखा प्रस्तुत करने में असफलता जानबूझ कर नहीं की गयी थी क्योंकि वह ऐसे कारण थे जिन पर उनका नियन्त्रण नहीं था, इनके निर्वाचन एजेन्ट, श्री जितेन्द्र कुमार सेठ ने न तो सम्बन्धित अधिकारी के पास लेखा प्रस्तुत किया और न ही श्री राजेश सिंह को लेखा चापिस किया

और इस प्रकार उन्होंने (श्री जितेन्द्र ने) उन्हें धोखा दिया। लेखे से सम्बन्धित रिकार्ड श्री जितेन्द्र कुमार (उनके निर्वाचन एजेंट) के घर से पुलिस की सहायता से बरामद कर लिए गए। इस दावे के समर्थन में सम्बन्धित रिकार्ड भी प्रस्तुत किया गया। स्वाभाविक न्याय के रूप में आयोग ने निर्णय लिया कि श्री राजेश सिंह को कानून द्वारा अपेक्षित अपने लेखा दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया जाना चाहिए; और

यतः, तदनुसार श्री राजेश सिंह को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया और आयोग के 19 फरवरी, 2003 के पत्र सं. उ.प्र.-वि.स./277/2002/449 द्वारा उन्हें सूचना दी गई; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर ने अपने दिनांक 4 मार्च, 2003 के पत्र सं. 106/29-(2002-2003)2003 में रिपोर्ट दी है कि श्री राजेश सिंह ने आयोग के निदेशों का पालन किया है और कानून द्वारा अपेक्षित विधि से ही अपना लेखा दाखिल किया है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 की 43) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन अपने दिनांक 7 नवम्बर, 2002 के आदेश द्वारा श्री राजेश सिंह पर लगाई गई निरहता एतद्वारा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2003 से शेष अवधि के लिए हटाता है।

[सं. उ.प्र.-वि.स./277/2002]

आदेश से,

ए. एन. झा, उप निर्वाचन आयुक्त

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2003

O. N. 31.—Whereas Shri Rajesh Singh, a contesting candidate at the General Election to Uttar Pradesh Legislative Assembly from 277-Sarsaul Assembly Constituency, held in February, 2002 was disqualified by the Election Commission of India for failure to file the account of election expenses vide its order No. 76/UP-LA/2002, dated 7th November, 2002, under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for three years from the date of that order on the basis of report of District Election Officer, Kanpur Nagar intimating non-submission of account of election expenses by the said candidate.

And, whereas, Shri Rajesh Singh had submitted a representation dated nil wherein he had submitted that he had not received any notice from the Commission;

And, whereas, as per the records, the Commission's notice, dated 15th July, 2002 was received by his sister Ms. Rectu Singh on 10th August, 2002;

And whereas, after considering the representation on its merits on the basis of the facts and information available, the Election Commission had rejected the appeal made by Shri Rajesh Singh;

And, whereas, Shri Rajesh Singh had again filed an appeal dated 17th December, 2002 under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 before the Commission and requested that the disqualification imposed upon him under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 vide Commission's order dated 7th November, 2002 be removed;

And, whereas, after considering the further information provided in the fresh appeal dated 17th December, 2002 the Commission had decided to afford an opportunity of being heard in person to Shri Rajesh Singh and fixed the hearing for 5th February, 2003;

And, whereas, after hearing Shri Rajesh Singh on 5th February, 2003, the Commission had concluded that the failure to submit the accounts of election expenses by Shri Rajesh Singh was not intentional and was beyond his control as his election agent Shri Jitender Kumar Seth had cheated him by, neither submitting the accounts with concerned officers nor returning the same to Shri Rajesh Singh. The records relating to the accounts were reportedly recovered from the residence of Shri Jitender Kumar (his election agent) with the help of the Police. Relevant records in support of this claim were also produced. In the interest of natural justice the Commission decided that Shri Rajesh Singh should be given another opportunity to lodge his accounts as required by law;

And, whereas, accordingly a final opportunity was afforded to Shri Rajesh Singh and was communicated to him vide Commission's letter No. UP-LA/277/2002/449, dated 19th February, 2003;

And, whereas, the District Election Officer, Kanpur Nagar, had vide his letter No. 106/29-(2002-2003)2003, dated 4th March, 2003 reported that Shri Rajesh Singh had complied with the Commission's directions and had filed his accounts in the manner required by law;

And, now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby removes the disqualification of Shri Rajesh Singh imposed upon him by the Commission's Order dated 7th November, 2002 under Section 10A of the said Act, for the remaining period w.e.f. 18th March, 2003.

[No. UP-LA/277/2002]

By Order,

A. N. JHA, Dy. Election Commissioner

नई दिल्ली, 14 मई, 2003

New Delhi, the 14th May, 2003

आ. अ. 32.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री अजय सिंह, आई.ए.एस. के स्थान पर डॉ. के.के. चक्रवर्ती, आई.ए.एस. (1970), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. डॉ. के.के. चक्रवर्ती को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ के रूप में कार्य करते हुए सचिव, शिक्षा, वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचन की घोषणा के तुरन्त बाद वे उपरोक्त अतिरिक्त प्रभारों को धारण करना समाप्त कर देंगे और तत्काल सौंप देंगे।

[सं. 154/छत्तीसगढ़/2003-का. प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, अवर सचिव

O. N. 32.—In exercise of the power conferred by Sub-section (I) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Chhattisgarh hereby nominates Dr. K.K. Chakravarty, IAS (1970), as the Chief Electoral Officer for the State of Chhattisgarh with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Ajay Singh, IAS.

2. Dr. K.K. Chakravarty while working as Chief Electoral Officer, Chhattisgarh is allowed to retain the charge of Education, Forests and Culture Departments. He shall cease to hold and hand over forthwith the said additional charges immediately after the announcement of elections in the State of Chhattisgarh.

[No. 154/CGH/2003-P. Admn.]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.